आई टी ई सी के 50 वर्ष

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम भारतीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा 15 सितंबर, 1964 से शुरू किया गया। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपने निर्णय से अवगत कराते समय मंत्रिमंडल ने नोट किया था कि "परस्पर लाभ के लिए साझेदारी एवं सहयोग के आधार पर अन्य विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों के विकास के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम आवश्यक है। यह उनके लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उनके साझे लक्ष्य की प्राप्ति में इसके सभी सदस्यों की परस्पर निर्भरता के आधार पर विश्व समुदाय के उद्भव में योगदान करने संबंधी हमारे संकल्प का एक ठोस प्रमाण भी होगा।" तभी से 15 सितंबर को हर साल आई टी ई सी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आई टी ई सी एवं इसके सहोदर कार्यक्रमों अर्थात एस सी ए ए पी (अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम), तथा कोलंबो प्लान की तकनीकी सहयोग स्कीम के तहत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 6 से अधिक दशकों में अर्जित इसके विकास संबंधी अनुभव को साझा करने के लिए 160 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जाता है।

हालांकि खुद आई टी ई सी कार्यक्रम की शुरूआत 1964 में ही हुई, परंतु भारत की विकास सहयोग नीति के आधार पर "एक विश्व" का वृहत्तर विजन भारत की आजादी के तुरंत बाद आरंभ हो गया था। 1949 में ही भारत ने भारत में पढ़ाई करने के लिए अन्य विकासशील देशों के छात्रों के 70 छात्रवृत्तियों की घोषणा कर दी थी। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, यह दृढ़ धारणा व्याप्त थी कि कुछ आर्थिक एवं अन्य प्रिस्क्रिप्शन जो प्राप्त सहायता के साथ आते हैं, प्रचलित सामाजिक - आर्थिक स्थितियों पर लागू नहीं थे।

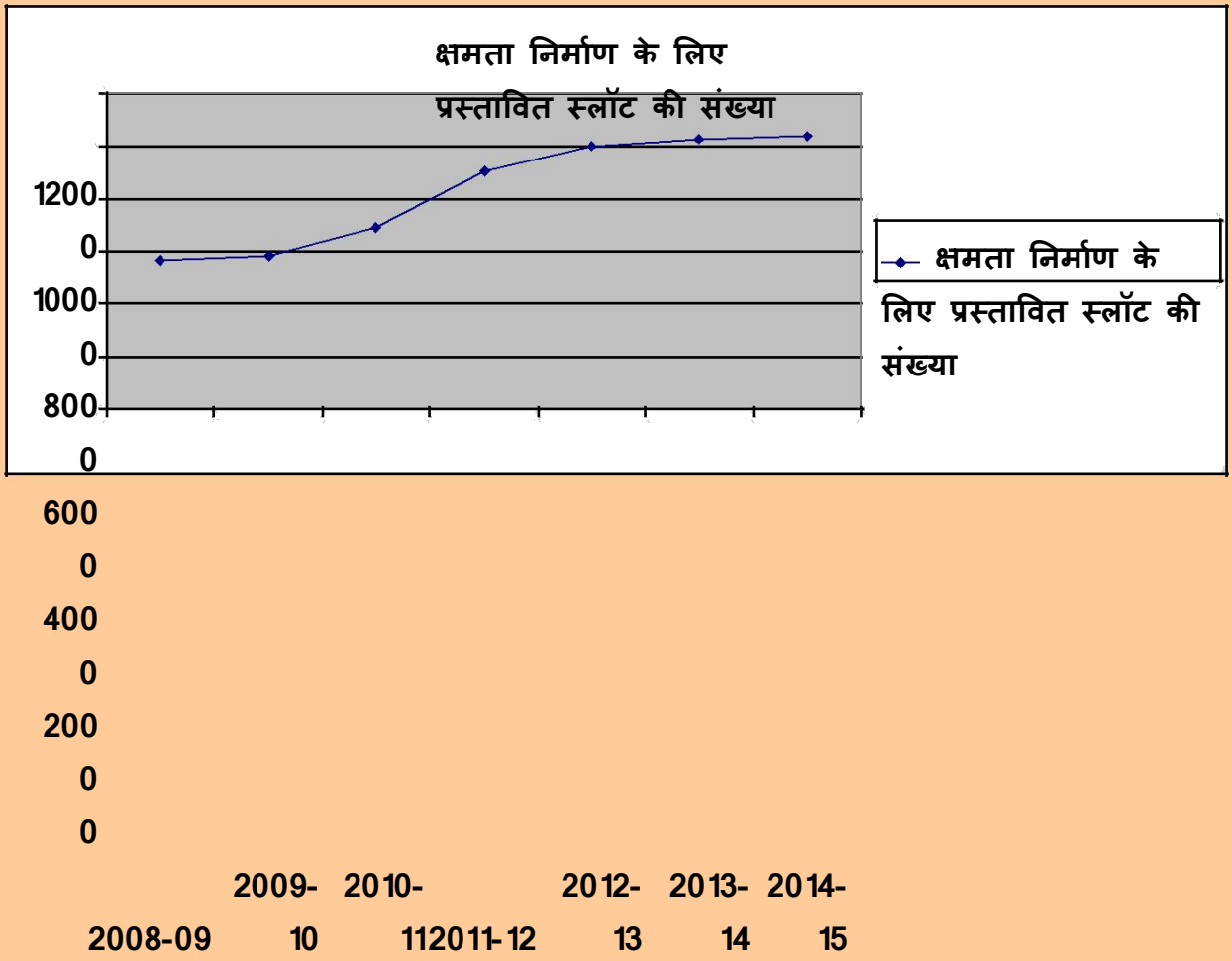
क्षमता निर्माण के लिए
प्रस्तावित स्लॉट की संख्या
1200
0
1000
0
800
0
600
0
400
0
200
0
0
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
क्षमता निर्माण के लिए प्रस्तावित स्लॉट की संख्या

इसके अलावा, क्षमता निर्माण के लिए जो सहायता प्राप्त होती थी वह अमूल्य थी तथा भारत के विकास पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। यह आई टी ई सी के लिए प्रेरणा का स्रोत था - सही मायने में उद्देश्य यह था कि विकास के संबंध में हमें जो सबक मिल रहे हैं उनको साझा किया जाए। इस विश्वास के आधार पर, विभिन्न मंचों पर तथा वाद - विवाद में जिसमें दक्षिण - दक्षिण सहयोग (जैसे कि अंकटाड, ई सी डी सी यानी विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग, टी सी डी सी यानी विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि) शामिल थे, भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई।

आई टी ई सी की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या में दर्शाया गया है। 2013-14 में, आई टी ई सी / एस सी ए ए पी कार्यक्रम के तहत 10000 से अधिक छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई; भारत में 47 ऐसे प्रशिक्षण संस्थान हैं जो विविध क्षेत्रों में जैसे कि आई टी, लोक प्रशासन, चुनाव प्रबंधन, एस एम ई, उद्यमशीलता, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, नवीकरणीय ऊर्जा आदि में 280 से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में रक्षा सेवा के तीनों विंग - थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना को शामिल करते हुए रक्षा कर्मियों के लिए सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, समुद्री एवं वैमानिक इंजीनियरिंग, संभार तंत्र एवं प्रबंधन, समुद्री जल विज्ञान, बगावत से निपटना आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सुविधा स्वयं वित्त पोषण के आधार पर कुछ विकसित देशों को भी प्रदान की जाती है तथा इसका वे लाभ उठा रहे हैं। आई टी ई सी पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को न केवल पेशेवर कौशल प्रदान करते हैं अपितु उनको उत्तरोत्तर भूमंडलीकृत विश्व के लिए भी तैयार करते हैं।

प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि की वजह से आई टी ई सी के लिए बजटीय आबंटन में भी वृद्धि हो रही है; यह 1964-65 में 4.46 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 1971-72 में 1 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, और 2013-14 में यह और बढ़कर 200 करोड़ रुपए से अधिक हो गया (आई टी ई सी + एस सी ए ए पी + कोलंबो प्लान)

आई टी ई सी कार्यक्रम की परिकल्पना मूल रूप से एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में की गई है। तथापि, हाल के वर्षों में आई टी ई सी के संसाधनों का प्रयोग क्षेत्रीय एवं अंतर्क्षेत्रीय संदर्भ में जैसे कि अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, राष्ट्रमंडल सचिवालय की औद्योगिक विकास यूनिट, यू एन आई डी ओ, जी-77 एवं जी-15 के तहत परिकल्पित सहयोग कार्यक्रमों के लिए भी किया गया है। हाल ही में इसकी गतिविधियों को क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों तथा सहयोग समूहों जैसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक), मेकांग - गंगा सहयोग (एम जी सी), अफ्रीकी संघ (ए यू), अफ्रीका - एशिया ग्रामीण

विकास संगठन (ए ए आर डी ओ), अखिल अफ्रीकी संसद, कैरेबियन समुदाय (कैरिकॉम), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ), हिंद महासागर परिधि - क्षेत्रीय सहयोग संघ (आई ओ आर - ए आर सी) तथा भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक के साथ भी जोड़ा गया है।

आई टी ई सी कार्यक्रम के अनेक घटक हैं। भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, यह विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, आपदा राहत के लिए सहायता, उपहार के तौर पर उपकरण देना, अध्ययन दौरा तथा संभाव्यता अध्ययन / परामर्शी सेवा आदि को भी कवर करता है। चूंकि आई टी ई सी मांग पर आधारित कार्यक्रम है, इसलिए आई टी ई सी के तहत प्रस्तावित सहायता आम तौर पर मैत्रीपूर्ण देशों से प्राप्त अनुरोधों तथा भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर आधारित होती है।

आई टी ई सी के तहत प्रदान किए जाने वाले नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, साथी देशों के विशिष्ट अनुरोध पर विशेष पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं / निर्धारित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में, नए क्षेत्रों में जैसे कि चुनाव प्रबंधन (आई आई डी ई एम यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में), सरकारी निष्पादन प्रबंधन (मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ), सिविल सेवकों का करियर मध्य प्रशिक्षण (एन आई ए आर अर्थात राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान / एन सी जी जी अर्थात राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में), शहरी अवसंरचना प्रबंधन (मानव बस्ती प्रबंधन संस्थान में), सुगंध एवं स्वाद अध्ययन (सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र में), डब्ल्यू टी ओ से संबंधित विषय (डब्ल्यू टी ओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में) में विशेष पाठ्यक्रमों का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, आई टी ई सी के तहत कुछ अभिनव पाठ्यक्रमों की भी पेशकश की जाती है जैसे कि बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया, राजस्थान में सबसे कम विकसित देशों की अर्ध साक्षर एवं निरक्षर ग्रैंड मदर्स के लिए सौर प्रौद्योगिकी पर पाठ्यक्रम।

वें आई टी ई सी पाठ्यक्रम के बेयरफुट कॉलेज के प्रतिभागी

टी ई आर आई - आई टी ई सी कार्यक्रम :
व्यापार एवं संपोषणीय विकास

विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान - आयोजना एवं कार्यान्वयन पर टी ई आर आई - आई टी ई सी कार्यक्रम

आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रक्रिया की शुरूआत तब होती है जब साथी देश से अनुरोध प्राप्त होता है जिसमें उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं का उल्लेख होता है तथा जब दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों / बाध्यताओं की पुष्टि हो जाती है। हाल के वर्षों में, अनेक क्षेत्रों में जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा, कानूनी मामले, कृषि, आयुर्वेद, सांख्यिकी एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन एवं वस्त्र में भारतीय विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया गया है। अनेक देशों द्वारा रक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की गई हैं। साथी देशों के अनुरोध पर संचालित किए गए

संभाव्यता अध्ययनों एवं परामर्शी सेवाओं के परिणाम नि:शुल्क रूप में संबंधित सरकारों को इस ढंग से प्रयोग करने के लिए सौंपे जाते हैं जो उनके द्वारा उपयुक्त समझा जाए।

भारत में अध्ययन दौरे के लिए, संबंधित भारतीय मिशन से परामर्श करके रूचि के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जाती है तथा एक - दो हफ्ते के कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है जिसके दौरान प्रतिनिधियों को भारत के विभिन्न भागों में स्थित महत्वपूर्ण संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, तथा रूचि के स्थानों पर ले जाया जाता है।

गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ 2005-06 के आई टी ई सी प्रतिभागी

आई टी ई सी ने अनेक महाद्वीपों में पुराने विद्यार्थियों के एक विशाल नेटवर्क का सृजन किया है जो अपने - अपने देशों में आई टी ई सी के पथ प्रदर्शक बन गए हैं और इस प्रक्रिया में भारत एवं संबंधित देश के बीच मजबूत सांस्कृतिक सेतु का निर्माण हुआ है। आई टी ई सी के पुराने विद्यार्थियों ने अपने लिए एक स्थान बनाया है तथा उनमें से कई मंत्री, वरिष्ठ राजनयिक, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी एवं अग्रणी उद्यमी बन गए हैं। आई टी ई सी के तहत विभिन्न गतिविधियों की वजह से तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञता प्रदान करने वाले देश के रूप में भारत की दक्षता के बारे में अन्य देशों में जागरूकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और बढ़ रही है। इन वर्षों में, इन कार्यक्रमों ने देश के लिए प्रचुर मात्रा में सद्भाव का सृजन किया है।

इस साल आई टी ई सी अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। अब तक तय की गई यात्रा, हासिल की गई उपलब्धियों तथा सामने खड़ी चुनौतियों पर चिंतन - मनन करने का यह उपयुक्त समय है। इस प्रक्रिया में जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हुआ है वह भारत को अधिक नवाचारी एवं कारगर ढंग से साथी विकासशील देशों तक पहुंचने में समर्थ बनाएगा।

******

आगे पढ़ें :

:/ / ..../